SILGO RETAIL LTD.
CIN : L36911RJ2016PLC049036

SIL/JAI/20-21

Date: August 27, 2020

To
National Stock Exchange India Limited
Exchange Plaza,
Plot No. C/1, G Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai- 400051

COMPANY NAME : SILGO RETAIL LIMITED

NSE EMERGE SYMBOL: SILGO

Subject: Intimation under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of the newspaper advertisement published in Economic Times (Jaipur, English edition) and Business Remedies (Jaipur, Hindi edition) on Thursday, August 27, 2020, confirming the dispatch of Postal Ballot Notice through e-mail, process for registration of email addresses, information related to remote e-voting and other details.

The copy of said newspaper advertisement is also available on the Company's website at www.silgo.in.

Kindly take the same on your record.

Yours truly,
For SILGO RETAIL LIMITED

SILGO RETAIL LIMITED

Tripti Sharma
Company Secretary
Membership no. A52232

विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा जमा सिक्योरिटी पर ब्याज में देरी से भुगतान की व्यवस्था सुधरवाने की मांग

बीकानेर। बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया, उद्योग संघ के विद्युतीय सलाहकार एम.एस. फगेरिया, हनुमान झंवर व सुनील झंवर ने जिला कलैक्टर नमित मेहता से मुलाकात कर बीकेईएसएल कंपनी द्वारा विद्युत उपभोक्त ाओं द्वारा जमा सिक्योरिटी पर ब्याज में देरी से भुगतान की व्यवस्था सुधरवाने बाबत ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया ने बताया कि बीकेईएसएल कंपनी द्वारा विद्युत उपभोक्त ाओं की जमा सिक्योरिटी पर उपभोक्त ा को मिलने वाले ब्याज को देने में अनावश्यक देरी की जा रही है, जबकि जोधपुर डिस्कोम द्वारा सिक्योरटी का ब्याज विगत 2015-16-17 में माह फरवरी में ही भुगतान कर दिया जाता था, लेकिन जबसे वर्ष 2017 के मई माह से बीकानेर के विद्युत विभाग को बीकेईएसएल कंपनी को सौंपा गया था तबसे वर्ष 2018 को यह सिक्योरिटी माह जुलाई में व 2019 को यह सिक्योरिटी अक्टूबर माह में उपभोक्त ा को दी गई, जो कि न्यायोचित नहीं है।

टेक्नोलॉजी और मनोविज्ञान जुड़े हुए हैं परस्पर : मुग्धा सिन्हा

फिक्की द्वारा 'फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी' पर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन

बिजनेस रेमेडीज/जयपुर। फिक्की राजस्थान स्टेट काउंसिल द्वारा ग्रीन मोबिलिटी 'एडवांटेज राजस्थान' थीम पर मोबिलिटी के भविष्य पर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य राजस्थान में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, मैन्यूफैक्चरिंग पॉसिबिलटीज़, इन्सेन्टिव्स, नए इन्फ्रास्ट्रक्चर की जरूरतों, उद्योग की अपेक्षाओं, क्षेत्र में विकास के अवसरों, इनोवेशन, उपभोक्त ाओं के व्यवहार परिवर्तन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन आदि पर विस्तार से चर्चा करना था।

इस दौरान राजस्थान सरकार के साईंस व टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की सैकेट्री मुग्धा सिन्हा ने अपने उद्बोधन में कहा कि यह लोगों का काम नहीं है कि वे मशीन के अनुरूप खुद को ढ़ालें, बल्कि मशीन और उनके निर्माताओं का यह काम है कि वे लोगों के अनुरूप खुद को अभिव्यक्त करें और यहीं बेहतरीन डिजाइन का मूलमंत्र है। मशीन और मनुष्य का मनोविज्ञान आपस में एक-दूसरे से जुड़े है। वर्तमान में निरंतर व्यापक हो रहे तकनीक जगत के अनुरूप हमें हमारी नीतियों का निर्माण करना है। भविष्य के परिचालन की आवश्यकता को इलेक्ट्रिक वाहनों तक ही सीमित नहीं किया जा सकता है। नीतियों का निर्माण डिजाईन के सिद्वांतों के अनुरूप तथा तेजी से परिवर्तनशीलता कारकों के अनुरूप होना चाहिये। इनको प्रेरित करने वाले सिद्वांत जीवन की गुणवता, शहरों की गुणवता और कार्यान्वयन में सुगमता होना चाहिये।

वास्तव में यह क्षेत्र इतना व्यापक है कि जहां एक तरफ इस क्षेत्र में हम आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑटोमेशन आदि के प्रयोग करने की बात करते है, वहीं दूसरी तरफ हम साइकिल के लिये अलग से निर्धारित रास्ता बनाने को भी महत्त्व देते है। विविध क्षेत्रों में सुगमता लाकर शहरों और इन शहरों में निवास करने वाले लोगों के जीवन में गुणवत्ता का स्तर बढ़ाया जा सकता है।

इसी प्रकार राजस्थान सरकार के परिवहन विभाग के सैकेट्री व कमीशनर रवि जैन ने अपने संबोधन में बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में पॉलीसी को प्रस्तुत करने वालों में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में से एक होने वाला है। इस संबंध में हम जल्द ही अपनी पॉलीसी लेकर आ रहे है। पर्यावरण हितैषी वाहनों के परिचालन को लेकर राज्य सरकार गम्भीर है और इसी वजह से उन्होंने इस संबंध में कई तरह की रियायतें व प्रोत्साहन कार्यक्रम प्रस्तुत किये है। वर्तमान में राजस्थान में लगभग 2 करोड़ वाहन पंजीकृत है और प्रतिमाह 1 लाख से अधिक वाहनों की बिक्री हो रही है इस संख्या को देखते हुए हमारी योजना भविष्यनोमुखी होनी चाहिये। इस संबंध में विविध रियायते देने के साथ हम लोग सार्वजनिक वाहनों के प्रयोग को भी बढ़ावा दे रहे है। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के अंतर्गत हमने इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू कर दिया है और आने वाले समय में हम राजस्थान रोड़वेज में भी इन बसों को प्रयोग करने जा रहे है। फिक्की नेशनल कमेटी ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल के चैयरमैन और टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के वाईस चैयरमैन शेखर विश्वानाथन ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों का भविष्य उज्जवल है, लेकिन साथ ही हमें इस बात को भी समझना होगा कि इसकी वृद्धि और स्वीकार्यता इसकी कीमतों और प्रर्दशन पर भी निर्भर करेगी। इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग में धीरे-धीरे वृद्धि होगी और ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2050 तक इनकी संख्या कुल वाहनों का 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत हो जायेगी। इसके साथ ही हम इससे संबंधित अन्य चुनौतियों जैसे लागत में बैट्री की कीमत का बड़ा हिस्सा होना, लिथीयम टेक्नोलॉजी पर अत्याधिक निर्भरता आदि पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

वहीं होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर प्रवीण परांजपे ने बताया कि राजस्थान में सड़क अवसंरचना को विकसित करने, राज्य के दूरस्थ भागों को जोड़ने और इसे मुख्यधारा बनाने में बहुत अधिक ध्यान केन्द्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी निदान दृष्टिकोण को अपनाना सफलता की कुंजी होगी। इसी प्रकार डिलॉयट इंडिया के ऑटोमोटिव सेक्टर के पार्टनर व लीडर राजीव सिंह ने बताया कि भविष्य में मोबिलिटी में बड़े पैमाने में बदलाव लाने में 5 प्रमुख कारकों-शहरीकरण, आर्थिक प्रगति, जलवायु परिवर्तन, उनभोक्त ाओं की पंसद में परिर्वतन तथा डिजीटलाइजेशन और तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आने वाले सालों में सरकारी अनुदान, पर्यावरण के प्रति लोगों की जागरूकता तथा बैट्री की कीमतों में कमी के कारण इलेक्ट्रीक वाहनों की ब्रिकी में उत्तरोतर वृद्धि होगी। इसके साथ चार्जिंग सुविधा में वृद्धि और संस्थापन से आय का एक नया साधन भी विकसित होगा।

वहीं फिक्की राजस्थान स्टेट काउंसिल के को-चैयरमैन और मंडावा होटल्स के सीएमडी रणधीर विक्रम सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री डिजिटलाइजेशन द्वारा संचालित व्यवधान के कगार पर है और विघटन के प्रभावों का अनुभव करना शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि विद्युतीकरण, साझा गतिशीलता, कनेक्टिविटी और स्वायत्त ड्राइविंग जैसे चार प्रौद्योगिकी संचालित टेंड इस व्यवधान के लिए उद्योग का नेतृत्त्व कर रहे हैं। उनके अनुसार ऑटोमोबाइल उद्योग वैश्विक और भारतीय स्तर पर विद्युतीकरण या ई-मोबिलिटी के प्रभावों को महसूस कर रहा है और 2030 तक इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को ऑटोमोबाइल क्षेत्र में पर्याप्त हिस्सेदारी मिल सकती है। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के अंत में, फिक्की राजस्थान सब-कमेटी ऑन एचआर एंड स्किल्स और होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के वीपी सुनील कुमार यादव ने धन्यवाद ज्ञापित किया और बताया कि भविष्य ग्रीन मोबिलिटी की गतिशीलता का है क्योंकि इन तकनीकों को अपनाने की दिशा में एक समृद्ध इच्छा, तकनीकी प्रगति और झुकाव दिखता है।

जीएसटी काउंसिल की बैठक से राज्यों को उम्मीदें

जयपुर। वस्तु एवं सेवा कर काउंसिल की 41 वीं बैठक 27 अगस्त को होगी। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए होने वाली बैठक से कारोबारियों और आमवर्ग को राहत की उम्मीद है। वहीं राजनीतिक लिहाज से भी बैठक में यूपीए समर्थित राज्य केंद्र को नीतिगत मसलों पर घेर सकते हैं। राजस्थान भी बकाया जीएसटी हिस्सा राशि के लिए अपना विरोध दर्ज करवा सकता है।

इस बैठक में राज्य कोरोना संक्रमण से प्रभावित अर्थव्यवस्था को गति देने के की मांग भी केंद्रीय वित्त मंत्रालय से करेंगे। बैठक में राज्यों के मुआवजा भुगतान और राजस्व में कमी को पूरा करने पर चर्चा हो सकती है।

जीएसटी को लागू किए जाने के बाद से अधिकतर चीजों पर लगने वाले टैक्स रेट में कमी की गई है। वित्त मंत्रालय के अनुसार अब 28 फीसदी के टैक्स स्लैब के अंतर्गत लग्जरी आइटम और डेट्रिमेंट्ल वस्तुएं ही रह गई हैं। इस टैक्स स्लैब के अंतर्गत 230 वस्तुएं थीं, लेकिन करीब 200 वस्तुओं को कम टैक्स वाले स्लैब में शिफ्ट कर दिया गया। अब 40 लाख रुपए तक के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को जीएसटी से छूट दी जानी है। शुरूआत में यह सीमा 20 लाख रुपए थी।

इसके अलावा 1.5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले कंपोजिशन स्कीम भी चुन सकते हैं और 1 फीसदी कर का भुगतान कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण और अर्थव्यवस्था की सुस्त रफ्तार को दूर करने के प्रावधानों की मांग पर भी निर्णय हो सकते है। वहीं कुछ राज्य केंद्र को जीएसटी भुगतान और राजस्व के मसले पर घेरने की तैयारी में है। राजस्थान भी कई महिनों की बकाया स्टेट जीएसटी राशि जारी करने की मांग जीउसटी काउंसिल में करेगा।

वर्चुअल बैठक में जीएसटी काउंसिल के सभी सदस्य और राज्यों के वित्त मंत्री जुड़ेंगे। माना जा रहा है वस्तु और सेवा कर परिषद दोपहिया वाहनों पर टैक्स कम करने के उद्योग के प्रस्ताव को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि यह न तो लक्जरी सामान में आता है और न ही डिमेरिट गुड है। इसका लाभ ऑटोमोबाइल सेक्टर को मिलेगा। अगर परिणाम अनुमानों के अनुसार रहे तो आमजनता की जेब पर राहत जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद संभव है।

नारायण सेवा संस्थान में महिला समानता दिवस पर विचार गोष्ठी आयोजित

उदयपुर। नारायण सेवा संस्थान में बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला समानता दिवस पर विचार गोष्ठी संस्थापक चैयरमेन कैलाश मानव और कमला देवी की सयुंक्त अध्यक्षता में आयोजित हुई। मानव ने कहा कि समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए महिलाओं को सशक्त कर समानता का अधिकार देना ही हम सब की जीत है।

महिला सशक्ति करण के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली वंदना अग्रवाल ने कहा कि हर एक सेक्टर में महिलाओं ने अपने कौशल से लोहा मनवाया है। समाज की हर महिला को अपनी शक्ति को पहचाना होगा। महिलाएं हर मोर्चे पर पुरुषों के बराबर है, चाहे वह देश चलाने की बात हो या फिर घर संभालने की। यहां तक सुरक्षा की जिम्मेदारी भी बेखूबी निभा रही हैं।

RAGHAV PRODUCTIVITY ENHANCERS LTD.

Reg. Office: Office No. 36, A-10 Central Spine, Alankar Plaza, Vidhyadhar Nagar, Jaipur-302023
CIN: L27109RJ2009PLC030511

Tel & Fax: 0141-2235760/761, E-mail: rammingmass@gmail.com, Website: www.rammingmass.com

30.06.2020 को समाप्त तिमाही के स्टेण्डअलोन अनांकेक्षित वित्तीय परिणाम

(रु. लाख में प्रति शेयर डेटा छोड़कर)

विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष
	30.06.20 (अनांकेक्षित)	31.03.20 (अंकेक्षित)	30.06.19 (अनांकेक्षित)	31.03.20 (अंकेक्षित)
प्रचालनों से कुल आय (निवल)	913.74	1514.44	1678.69	6682.49
अवधि के लिए (कर, असाधारण एवं/अथवा विशिष्टमदों के पूर्व#) निवल लाभ	76.04	237.33	323.14	1291.03
अवधि के लिए कर पूर्व (असाधारण एवं/ अथवा विशिष्ट मदों के पश्चात#) निवल लाभ	76.04	237.33	323.14	1291.03
अवधि के लिए कर पश्चात (असाधारण एवं/ अथवा विशिष्ट मदों के पश्चात#) निवल लाभ	58.40	175.75	246.08	943.80
अवधि के लिए कुल समग्र आय	58.40	172.61	246.08	940.66
समता अंश पूंजी (मुख मूल्य प्रति शेयर रु. 10/-)	1005.13	1005.13	1005.13	1005.13
आरक्षित निधियां, गत अवधि के अंकेक्षित तुलनपत्र में प्रदर्शित (पुर्नमूल्यांकन आरक्षित निधियों को छोड़कर)	-	-	-	3176.89
प्रति शेयर आय (रु. 10/- प्रत्येक) मूल एवं अवमिश्रित	0.58	1.75	2.45	9.39

नोट : **ए)** वित्तीय परिणाम लेखा समिति द्वारा समीक्षा किये गए हैं तथा कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा इसकी 25 अगस्त, 2020 को आयोजित सभा में स्वीकृत किये गए हैं। **बी)** उपरोक्त तिमाही के वित्तीय परिणाम सेबी (सूचीबद्धता एवं अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजेज के साथ दायर वित्तीय परिणाम के विस्तृत स्वरूप का एक उद्धरण है। तिमाही वित्तीय परिणाम विस्तृत प्रारूप में वेबसाईट **www.bseindia.com** पर उपलब्ध है। यह परिणाम कम्पनी की वेबसाइट **www.rammingmass.com** पर भी उपलब्ध है।

सी) # - लाभ एवं हानि परिणामों में असाधारण एवं/अथवा विशिष्ट मद Ind-AS नियम/AS नियम, जो भी लागू हो, के अनुसार समायोजित किये गए हैं।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से
कृते राघव प्रोडक्टिविटी एन्हेन्सर्स लिमिटेड
ह./-
राजेश काबरा
(प्रबन्ध निदेशक)
DIN : 00935200

स्थान : जयपुर
दिनांक : 25 अगस्त, 2020

'राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन को सही दिशा में ले जाने की आवश्यकता'

बीकानेर। बीकानेर दाल मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरसिंहदास मिमाणी, सचिव राजकुमार पचीसिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जयकिशन अग्रवाल, उपाध्यक्ष अशोक गहलोत, कोषाध्यक्ष हरिकिशन गहलोत व सह सचिव डूंगरमल प्रजापत ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि बीकानेर दाल मिल्स एसोसिएशन भारत सरकार द्वारा जारी अध्यादेश कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अध्यादेश 2020 का स्वागत करती है तथा वर्तमान में राज्य के कुछ संगठनों द्वारा उक्त अध्यादेश के विरोध में चलाए आंदोलन को दिशाहीन मानते हुए आंदोलनरत संगठनों से अनुरोध करती है कि राज्य की मंडियों का भविष्य बचाने के लिए केंद्र सरकार के उक्त अध्यादेश का विरोध ना करते हुए राज्य सरकार से मांग करनी चाहिए कि वर्तमान लागू मंडी शुल्क कृषक कल्याण शुल्क की दर को न्यूनतम किया जाए तथा आढत की दर को भी कम किया जाए, ताकि राज्य में मंडियों का अस्तित्व बना रहे। बीकानेर दाल मिल्स एसोसिएशन 'एक देश एक कर' की अवधारणा के तहत लागू उक्त अध्यादेश के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करती है।

बीकानेर दाल मिल्स एसोसिएशन राजस्थान खाद्य व्यापार संघ द्वारा उक्त अध्यादेश के विरोध में राज्य की दाल मीलों का समर्थन बताने का खंडन करती ह। बीकानेर दाल मिल्स एसोशियेशन का मत है कि राजस्थान खाद्य पदार्थ संघ को अपने आन्दोलन पर पुनर्विचार करते हुए मंडी शुल्क दर को कम करने के लिए राज्य सरकार के खिलाफ आन्दोलन को सही दिशा में ले जाने की आवश्यकता है

उत्तर पश्चिम रेलवे ने बिछाया सोलर पैनल का जाल, करोड़ों रुपयों का बिजली खर्च बचाया

जयपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे ने बिजली की बढ़ती खपत को देखते हुए अब अपने चारों मंडलों में सोलर पैनल का जाल बिछा दिया है। NWR का दावा है कि अब तक सोलर पैनल के सहारे वह करोड़ों रुपयों की बचत कर चुका है। अब तक 6973 किलोवाट के सोलर पैनल का जाल बिछा दिया गया है और ये मुहिम लगातार जारी है। NWR का लक्ष्य है कि आने वाले समय में सभी रेलवे स्टेशन सोलर पैनल से ही चलाए जाए।

प्रतिवर्ष 3.96 करोड़ की बचत : पर्यावरण और ऊर्जा संरक्षण के लिये उत्तर पश्चिम रेलवे 6973 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल लगाकर प्रतिवर्ष 3.96 करोड़ की बचत कर रहा है। ऊर्जा संरक्षण के साथ पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिये रेलवे भी लगातार सकारात्मक कदम उठा रहा है। इसमें परम्परागत संसाधनों के स्थान पर पर्यावरण अनुकूल माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जन सम्पर्क अधिकारी अभय शर्मा के अनुसार रेलवे अपने प्रयासों को गति प्रदान कर स्वच्छ पर्यावरण की

मुहिम को बढ़ाने के साथ-साथ राजस्व की भी बचत कर रहा है। इस जोन में पिछले कुछ समय से सौर ऊर्जा पर काफी कार्य किये गये हैं। इसी कड़ी में 6973 किलोवाट के पैनल लगाए जा चुके हैं। जोन के जयपुर और अजमेर स्टेशन पर 500-500 किलोवाट के पैनल लगाए गए हैं। वहीं जोधपुर स्टेशन पर 770 किलावाट का उच्च सोलर पैनल स्थापित किया गया है। जोधपुर वर्कशॉप पर 440 और मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय पर 230 किलोवाट का सोलर पैनल लगाया गया है। वहीं भगत की कोठी पर 250 किलोवाट, मारवा? जंक्शन पर 120 और क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर में 180 किलोवाट का सोलर पैनल लगाया गया है. इसके अलावा दूसरे छोटे जंक्शन पर भी सोलर पैनल स्थापित कर विद्युत उत्पादन किया जा रहा है.

आवश्यकता

बिजनेस रेमेडीज दैनिक समाचार पत्र को कोटा, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली में खबरों एवं विज्ञापन कार्य हेतु प्रतिनिधि की आवश्यकता है।

सम्पर्क करें

बिजनेस रेमेडीज

63/118, हीरा पथ, मानसरोवर, जयपुर -302020
0141-2785686 ,9929106227
E-Mail: remediesbusiness@gmail.com
businessremedies@yahoo.com

सधा जीवन

जिसके हाथों में विश्व का निर्माण होता है, चारों ओर प्रसन्नता की अबीर गुलाल बरसती है। चाहे हजारों शोले बरसाये, कांटे बिखेरे उनकी जिंदगी से हर तीखापन मुलायम हो उठता है। द्वेष (विद्वेष) क्लेश के आंधी तूफां उसका रास्ता धुंधला नहीं कर सकते, वो उन्हें पारदर्शी बना चेतना की तह तक ले जाते है और उनकी नजर पर नजर रखने वाला उनके दिव्य संकेत, संदेश और सीख से स्वयं को साध लेता है। सधा हुआ हर कदम, सधा हुआ हर हाथ साधना को शिखर छू लेता है। आज विश्व को तलाश है ऐसे सधे जीवन की। हमें विश्वास है आप सधे जीवन की खोज में नंबर 1 टॉप बनेंगे।

चिंतनशीला वसुमति जी मा.सा.

फोरम एवं इवेंट इंडस्ट्री से जुड़े संस्थानों द्वारा 'अनुरोध मार्च' का आयोजन

इवेंट इंडस्ट्री को जल्द शुरू करने की रखी मांग

बिजनेस रेमेडीज/जयपुर। फोरम एवं इवेंट इंडस्ट्री की अन्य संस्थाओं की ओर से कोविड.19 के नियमों का पालन करते हुए एक 'अनुरोध मार्च' आयोजित किया गया। होटल हवेली की पार्किंग में आयोजित इस कार्यक्रम में सभी कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुख्य रूप से इस अनुरोध मार्च के जरिए इवेंट इंडस्ट्री से जुड़े सभी लोगों द्वारा सरकार से यह अनुरोध किया गया कि यदि इवेंट इंडस्ट्री को जल्द ही शुरू नहीं किया गया तो देश के लिए सर्वाधिक टैक्स संकलित करने वाली एक इंडस्ट्री जल्दी ही संकट में आ जाएगी। अतः पुनः इवेंट इंडस्ट्री को शुरू करें।

इस दौरान हरप्रीत बग्गा अध्यक्ष फेडरेशन ऑफ राजस्थान इवेंट

मैनेजर्स ने बताया कि इस 'अनुरोध मार्च' का उद्देश्य इवेंट संस्थाओं एवं इवेंट से जुड़े लोगों से जुड़ी वर्तमान समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। उन्होंने कहा कि एक लम्बे लॉकडाउन एवं कोरोना से लड़ने के लिए उठाये गए कदमों के कारण जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं उसका सबसे ज्यादा प्रभाव इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री पर पड़ा है, आज स्थिति यह है कि लाखों की संख्या में इवेंट इंडस्ट्री के लोग पिछले 6 माह से बेरोजगारी का गंज झेल रहे हैं। उन्होंने बताया कि इवेंट इंडस्ट्री में राजस्थान के लगभग 13. 30 लाख लोग सीधे जुड़े हुए हैं, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से यह संख्या बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में टेंट व्यवसाई, कैटरिंग, टूरिज्म, डेकोरेशन, गिफ्ट आर्टिकल, कैंडल डेकोरेशन, होटल, विवाह स्थल, ढोल शहनाई, बैंड बाजा, जनरेटर, लाइट जैसे अनेकानेक व्यवसाय भी शामिल हैं। इस कार्यक्रम के जरिये समस्त इवेंट इंडस्ट्री की ओर से सरकार से ये गुजारिश है कि वह एक गाइडलाइन बनाएं, जिसके तहत इवेंट्स मैनेजमेंट का व्यवसाय पुनः शुरू हो सके। साथ ही यह आश्वासन भी दिलाया कि सम्पूर्ण इवेंट इंडस्ट्री सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों का पालन करते हुए ही भावी कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। इन्हीं परिस्थितियों से सरकार को अवगत कराने हेतु इस कार्यक्रम में मीडिया से जुड़े लोगो को भी आमंत्रित किया गया। इस दौरान मीडिया को सम्बोधित करते हुए मोहित माहेश्वरी महासचिव फेडरेशन ऑफ राजस्थान इवेंट मैनेजर्स ने कहा कि जिस प्रकार से एक फ्लाइट में सैंकड़ों लोग नियमों का पालन करते हुए एक साथ जा सकते हैं उसी तर्ज पर इवेंट्स भी शुरू किए जाने चाहिए और तय शर्तों के साथ इवेंट्स को पुनः शुरू करने की अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया।

सिल्गो रिटेल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः बी-11, महालक्ष्मी नगर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302017
दूरभाष नं.: 0141-4919655, वेबसाईटः www.silgo.in, ई-मेलः info@silgo.in
सीआईएनः **L36911RJ2016PLC049036**

सूचना

कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 110 और 108 सपठित कंपनीज (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 और नियम 22 (जिसमें कोई वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमित के समय लागू हो) और अन्य कोई कंपनी अधिनियम 2013 का प्रावधान लागू हो, की अनुपालना में सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचियां दायित्व व प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और इस प्रकार के अन्य नियम व विनियम जो भी लागू हों, कंपनी पोस्टल बैलट के माध्यम से सदस्यों से मंजूरी प्राप्त करना चाह रही है (केवल रिमोट ई-वोटिंग के लिए) कि प्रवर्तक व अन्य को प्रस्तावित प्रेफरेंशल इश्यू 40 रुपये इश्यू कीमत पर 10 रुपये फेसवेल्यू के 1,550,000 इक्विटी शेयर विशेष प्रस्ताव के माध्यम से आवंटित किये जायेंगे, इसका विवरण दिनांकित 21 अगस्त, 2020 को पोस्टल बैलट की सूचना के अनुसार निर्धारित है।

कारपोरेट मामलात मंत्रालय, भारत सरकार (एमसीए परिपत्रों) द्वारा कोविड-19 के भय को देखते हुए जारी किये गये सामान्य परिपत्र नं.14/2020 दिनांकित 8 अप्रेल 2020, सामान्य परिपत्र नं.17/2020 दिनांकित 13 अप्रेल 2020 और सामान्य परिपत्र नं.22/2020 दिनाकिंत 15 जून 2020 के अनुसार पोस्टल बैलट की सूचना मय व्याख्यात्मक ब्यौरा केवल ई-मेल के माध्यम से 26 अगस्त, 2020 को उन सदस्यों को, जिनका नाम रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल), सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा 21 अगस्त,2020 (कट-ऑफ डेट) को सदस्यों/लाभकारी स्वामी के रजिस्टर में था और जिनका ई-मेल पता कंपनी/डिपॉजिटरिज के पास उपलब्ध था, को भेजा गया था। पोस्टल बैलट नोटिस के नोट्स भाग में ई-वोटिंग की प्रक्रिया दी गई है। पोस्टल बैलेट के नोटिस की हार्ड कॉपी, पोस्टल बैलट फॉर्म और प्रीपेड बिजनेस उत्तर लिफाफे के साथ शेयरधारकों को नहीं भेजी जाएगी और शेयरधारकों को उनकी मंजूरी या नामंजूरी को केवल रिमोट ई-वोटिंग के जरिये ही संचारित करने की प्रार्थना है। पेस्टल बैलट का नोटिस मय व्याख्यात्मक ब्यौरा व अन्य अनुबंध कंपनी की वेबसाईट **www.silgo.in**, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड के '' इमर्ज प्लेटफॉर्म'' की वेबसाईट **https://www1.nseindia.com/emerge/** और सीडीएसएल (रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के लिये कंपनी द्वारा नियुक्त एजेंसी) की वेबसाईट **www.evotingindia.com** पर भी उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 108 और कंपनीज (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम,2014 के नियम 20 और सेबी (सूचियां दायित्व व प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की अनुपालना में कंपनी को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा शेयरधारकों को उपलब्ध करवाकर प्रसन्नता है। कंपनी ने सुरक्षित तरीके से ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड की सेवाएं ली है और साफ व पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग की प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए शरत कुमार के शेट्टी एसोसिएट्स, पेशवर कंपनी सचिव को सविंक्षक के तौर पर नियुक्त किया है। कट ऑफ दिनांक को सदस्य (यों) के नाम (मों) की पंजीका में शेयर की पेडअप वेल्यू के अनुसार वोटिंग अधिकार तय किये जायेंगे।

ई-वोटिंग की समयावधि गुरूवार, 27 अगस्त,2020 को सुबह 9 बजे (आईएसटी) को शुरू होकर शुक्रवार , 25 सितम्बर, 2020 को सांय 5 बजे (आईएसटी) तक रहेगी। इसके बाद सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग का मापांक निर्योग्य कर दिया जायेगा। शेयरधारकों से प्रार्थना है कि वें अपना मत केवल निर्धारित समयावधि में ही देंवे और ई-वोटिंग की प्रक्रिया व रीति के बारे में ई-वोटिंग के निर्देशों को देंखे। एक बार शेयरधारक अपना मत दे देता है तो इसके बाद शेयरधारकों को इसमें बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी।

अन्य किसी जानकारी के लिए आप शेयरधारकों के लिए निर्मित अधिकत्तर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) खंड को देख सकते हैं, जो कि **www.evotingindia.com** के अर्न्तगत मदद भाग में उपलब्ध है या **helpdesk.evoting@cdslindia.com** या cs@silgo.in पर ई-मेल करके या कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी कुमारी तृप्ति से (0141-4919655) पर संपर्क कर सकते हैं या सीडीएसएल के अधिकारी श्रीमान नीतिन कुंदर (022-23058738) या श्रीमान राकेश दलवी (022-23058542) या श्रीमान महबूब लखानी (022-23058543) पर , जो इलेक्ट्रोनिक माध्यमों से शिकायतों का समाधान करेंगे, से संपर्क कर सकते हैं।

टिप्पणी (के1): पोस्टल बैलट और नोटिस की जानकारी के लिए प्रतिउत्तरित ई-मेल आईडी उपलब्ध करवायें, इसमें सीएस का विवरण हो सकता है।

टिप्पणी (एसएस2): कृप्या सीडीएसएल या तृप्ति शर्मा शर्मा से पुष्टि करें।

उन शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग की लॉगइन की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रकिया, जिनका ई-मेल पता डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं है।

1. अस्थाई पंजीकरण के लिए-जिन शेयरधारकों का ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है और नोटिस के संबंध में उनके साथ किसी भी कारण से संवाद स्थापित नहीं हो पाया है,वें कंपनी के आरटीए बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई गई लिंक **https://bigshareonline.com//InvestorRegistration.aspx.In** पर पंजीकरण करवाकर नोटिस और पोस्टल बैलट के लिए सक्षम बनाने वाली ई-वोटिंग की प्रक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। किसी अन्य जानकारी के लिए शेयरधारक **cs@silgo.in** पर ई-मेल लिख सकते हैं।

2. स्थाई पंजीकरण के लिए- ई-मेल पते के स्थाई पंजीकरण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि, सदस्यों से प्रार्थना है कि वें डीमेट होल्डिंग के संबंध में संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) के पास अपनी ई-मेल को पंजीकृत करवाएं और फिजिकल होल्डिंग के संबंध में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स और कंपनी आरटीए द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कंपनी आरटीए को अवगत कराएं।

3. ईमेल आईडीयों की मान्यता- जिन शेयरधारकों ने पहले से ही अपना ईमेल आईडी पंजीकृत करवा रखा है, उनसे प्रार्थना है कि वें अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स/ कंपनी के आरटीए से अपना ईमेल आईडी मान्य करवा लें, जिससे ईमेल पते पर नोटिस/कागजात/वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिकली प्राप्त हो सके।

जिन शेयरधारकों ने अपनी ई-मेल पता या तो कंपनी, कंपनी के आरटीए या उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) के पास पंजीकृत नहीं करवाया है, उनसे प्रार्थना है कि वें उपर्युक्त तरीके से अपना पंजीकरण करवायें। शेयरधारकों से प्रार्थना है कि वें डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ बिगशेयर प्राईवेट लिमिटेड, कंपनी आरटीए पास क्रमशः डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स या आरटीए द्वारा निर्धारित प्रक्रिया की अनुपालना करते हुए डीमेंट होल्डिंग के संबंध में अपना ई-मेल पता पंजीकृत करवायें।

संविक्षक अपना विवरण कंपनी के चेयरमैन या अन्य वह व्यक्ति तो उनके द्वारा अधिकृत किया गया हो, को दाखिल करेगा। शनिवार, 26 सितम्बर,2020 से पहले कंपनी के चेयरमैन या अन्य वह व्यक्ति जो उनके द्वारा अधिकृत किया गया हो, द्वारा पोस्टल बैलट के परिणाम घोषित किया जायेगा। पोस्टल बैलट के परिणाम मय संविक्षक विवरण कंपनी की वेबसाईट **www.silgo.in** और सीडीएसएल की ईवोटिंग वेबसाईट जैसे **www.evotingindia.com** पर प्रसारित किये जायेंगे। इसके साथ ही समान प्रकाशन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के ''इमर्ज प्लेटफॉर्म'' जहां पर कंपनी का शेयर सूचिबद्ध है, पर भी होगा।

सिल्गो रिटेल लिमिटेड के लिए

एसडी/-
तृप्ति शर्मा
कंपनी सचिव
स्थानः जयपुर
दिनांकः 27 अगस्त, 2020

rameters including the export

...st Growth ...Any Quarter

re responsive to easing of restrictions.

Such differences were not limited to demand and supply. Rural consumption grew faster than its urban counterpart while the industrial sector (81%) recovered faster than services (20.2%), said Nomura. In terms of August data, the NIBRI remained constant for the past two weeks. While mobility data was mixed, other indicators such as labour participation rate and power demand dropped for the second week in a row, said Nomura.

Petrol Prices Increase ₹10.5 per litre in 3 Mths

New Delhi: Petrol prices have risen by ₹1.3 per litre in the last 10 days and by Rs 10.5 per litre in three months. On Wednesday, petrol cost Rs 81.73 a litre in Delhi and Rs 88.39 in Mumbai. Diesel prices have remained unaltered in August after rising to a record in July. Diesel cost Rs 73.56 a litre in Delhi and Rs 80.11 in Mumbai on Wednesday. Until earlier this year, state oil companies used to daily align domestic rates of petrol and diesel with international prices but in the past six months they have ignored this practice.

Domestic fuel prices are high despite low international rates mainly due to steep tax increases this year. High diesel prices, along with extended lockdown and sluggish economic recovery, have contributed to a sharp drop in diesel demand in July-August, according to industry executives. – **Our Bureau**

TENDER NOTICE

Exciting Opportunity at Termin... Domestic, IGI Airport, Delhi, India ... set up, operate, maintain & manage ... CIP Lounge. To procure RFP docum... please send email request to 'Offic... Chief Commercial Officer-DIAL' ... **dial.rfp@gmrgroup.in** and sub... documents as mentioned on ... website. The last date to request for RFP is **3rd September 2020.**

Delhi International Airport Limited
Registered Office : New Udaan Bhawan, Opp Terminal 3, Indira Gandhi Internation... Airport, New Delhi – 110 037
www.newdelhiairport.in

Note: Advertisement dated 21st August ... issued on the subject matter, stan... superseded by this advertisement.

DIAL / 131 / PREM ASSOCIAT...

PUBLIC ANNOUNCEMENT

Before the Hon'ble National Company Law Tribunal Ahmedabad Bench case no CP(I.B.) no 509/ NCLT/AHM/2018

In the matter of M/S Orient Spa Limited (in Liquidation)

List of stakeholders under Regulation 31 of IBBI (Liquidation Process) Regulations, 2016 filed by CA Vikash Gautamchand Jain, liquidator of M/S Orient Spa Limited under the insolvency and Bankruptcy Code, 2016

1. The application for liquidation of the Corporate Debtor M/S Orient Spa Limited was filed by the Resolution Professional under the section 33(2) of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 read with Rule 7 of Insolvency and Bankruptcy (Application to Adjudicating Authority) Rules 2016 was admitted by Hon'ble National Company Law Tribunal Ahmedabad Bench vide order no IA 96 of 2020 in CP (I.B.) no 509/ NCLT/AHM/2018 dated 29.06.2020 wherein CA Vikash Gautamchand Jain, the undersigned was appointed as liquidator of M/S Orient Spa Limited who is directed to take necessary actions in accordance with the relevant provisions of the Insolvency and Bankruptcy Board of India.
2. In Compliance with Regulation 31 of Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations 2016, a category wise list of Stakeholders along with detail of stakeholder, amount claimed, claims admitted, proof admitted or rejected in part or whole, debt to the extent secured or unsecured in respect of claims is enclosed at Annexure A.

CA Vikash Gautamchand Jain
(IP Registration no: IBBI/IPA-001/IP-P00354/2017-18/10612)
Liquidator- Orient Spa Limited

Place: Ahmedabad
Date: 27.08.2020

Department of Commerce & Industries

Office of the Principal Secretary to Government, C&I Department

1st Floor, Vikasa Soudha, Dr. B R Ambedkar Road, Bengaluru-01. Tel.: 080-22034625, Fax : 080-22259870

No: C&I/Fertilizer/PPP/2019-20(2) **Date: 27.08.2020**

Inviting Expression of Interest for setting up Green Field Urea Project in Karnataka under PPP mode (Call-2)

Government of Karnataka through Department of Commerce and Industries proposes to set up a Green Field Urea Project at Kurubarahalli-Sarati, Davanagere District in Karnataka with the support from Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India through PPP mode.

State Government will provide the required land as its contribution to the project, to be set up under PPP mode and the entire investment for setting up of Fertilizer Plant has to be borne by the private entity / sector.

Private sector investors interested and capable for investing and setting up the proposed project are invited to send their Expression of Interest (EoI) for consideration by the Government.

Interested investors may visit the website of TECSOK (**www.tecsok.com**) for more details and format of Application. The last date for sending EoI is **30.09.2020.**

Department of C&I reserves the right to take appropriate decisions in the matter, without assigning any reasons, whatsoever.

Sd/- Director (Technical Cell)
C&I Department

SILGO RETAIL LIMITED

Regd. Office: B-11, Mahalaxmi Nagar, Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur -302017 , Rajasthan, India. Phone :0141- 4919655, Website :www.silgo.in, Email : info@silgo.in **CIN : L36911RJ2016PLC049036**

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Section 110 and 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 and 22 of Companies (Management and Administration) Rules 2014 (including any statutory modification or re – enactment thereof for the time being in force) and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 if any, the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and such other rules and regulation as may be applicable, the Company is seeking approval of its members through Postal Ballot (only through remote e-voting) by way of Special Resolution for the proposed preferential issue of 1,550,000 equity shares of face value of Rs. 10 at an issue price of Rs. 40 per equity share to promoters and others, the details which are set out in the Notice of Postal Ballot dated August 21, 2020.

Pursuant to General Circular No. 14/ 2020 dated 8 April 2020, General Circular No. 17/ 2020 dated 13 April 2020 and General Circular No. 22/ 2020 dated 15 June 2020 on account of the threat posed by COVID - 19" issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India ("MCA Circulars"), the Notice of Postal Ballot along with Explanatory statement was sent on August 26, 2020 via email only to the members whose name appear in the Register of Member / Beneficial owner received from Registrar and Share Transfer Agent, National Securities Depository Limited (NSDL), Central Depository Services Limited **(CDSL)** as on August 21, 2020 **(Cut- off date)** and whose email address are available with Company / Depositories. The procedure for e-voting is given in the notes forming part of the Postal Ballot Notice. The hard copy of Notice of Postal Ballot alongwith Postal Ballot Form and Prepaid Business reply envelop will not be dispatched to shareholders and shareholders are requested to communicate their assent or dissent through remote e-voting only. The Notice of Postal Ballot along with the explanatory statement and other annexures is also available on the website of the Company at **www.silgo.in**, website of the Stock Exchange i.e. National Stock Exchange of India Limited "Emerge Platform" at **https://www1.nseindia.com/emerge/** and on the website of CDSL (agency appointed by the Company for providing the Remote e-Voting facility) i.e. **www.evotingindia.com**

In Compliance with Section 108 of the Companies Act,2013 and rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules 2014 and regulation 44 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide remote e-voting facility to the shareholders of the Company. The Company has engaged the service of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for providing e-voting facility in a secure manner and has appointed Sharat kumar K Shetty & Associates, Practicing Company Secretary as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. The voting rights shall also be reckoned on the paid-up value of shares registered in the name(s) of the Member(s) as on the cut-off date.

E-voting period will commence on Thursday, August 27, 2020 at 9.00 A.M. (IST) and end on Friday, September 25, 2020 at 5.00 P.M.(IST). The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. The Share holders are requested to cast their votes during this period only and to refer the E-voting instructions in the postal ballot notice regarding the process and manner for E-voting. Once the vote is cast by the share holder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Share holders and e-voting user manual for Share holders available at www.evotingindia.com under the help section or call on 1800225533 or write an email to **helpdesk.evoting@cdslindia.com** or to **cs@silgo.in** or contact Ms. Tripti Sharma, Company Secretary & Compliance Officer, (0141-4919655) or to CDSL officers namely Mr. Nitin Kunder (022-23058738) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542) or Mr. Mehboob Lakhani (022- 23058543) who will address the grievances connected with the voting by electronic means.

PROCESS FOR THOSE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL ADDRESSES ARE NOT REGISTERED WITH THE DEPOSITORIES FOR OBTAINING LOGIN CREDENTIALS FOR REMOTE E-VOTING:

I. **For Temporary Registration:** The Shareholders who have not registered their e-mail addresses or have not received any communication regarding this Notice for any reason whatsoever, may obtain this Notice and the procedure for E-voting to enable e-voting for the Postal Ballot by registering their e-mail addresses using the link provided by Bigshare Services Private Limited, RTA of the Company i.e. https://bigshareonline.com/InvestorRegistration.aspx. In case of any queries, shareholder may write by sending an e-mail to cs@silgo.in.

II. **For Permanent Registration:** It is clarified that for permanent registration of e-mail address, the Members are requested to register their e-mail address, in respect of demat holdings with the respective Depository Participant (DP) and in respect of physical holdings, with the RTA of the Company by following the procedure prescribed by the Depository Participant or the RTA, respectively.

III. **Validation of e-mail Ids** :Those members who have already registered their e-mail address are requested to keep their e-mail addresses validated with their Depository Participants / the Company's RTA, to enable servicing of notices / documents / Annual Reports electronically to their e-mail address.

The Scrutinizer shall submit his report to the Chairman of the Company or to any other person authorised by him. The result of the Postal Ballot shall be declared by the Chairman or any other person authorized by him on or before Saturday, September 26, 2020. The result of the Postal Ballot along with the Scrutinizer's Report will be placed on the Company's website i.e. www.silgo.in and on the e-voting website of CDSL i.e. **www.evotingindia.com**. The same shall simultaneously be communicated to the National Stock Exchange of India Limited "Emerge Platform", on which the equity shares of the Company are listed.

Place: Jaipur
Date: August 27, 2020

For Silgo Retail Limited
Sd/- Tripti Sharma
Company Secretary

...R NOTICE

...nnur District - ...adannappalli- ...hs-Phase II- ...00 - 500000. ... 18.09.2020,

...a.gov.in Sd/- ... PH Circle, Kannur

...RICITY ...LIMITED

...ate: 26.08.2020

... eligible bidders ...GIS Sub Station at ...GIS Sub Station ...Sub Station along ... obtain bidding ...tenders.gov.in ... 26.08.2020 at ... Also visit the

Auction Sale Date & Time 28/09/2020 11:30 AM

... website i.e.

...orised Officer